अपने जीवन में गलती हर व्यक्ति करता है, इस गलती से कोई तो निखर जाता है और कोई बिखर जाता है।–अज्ञात।

विचार-प्रवाह
देहरादून, रविवार, 24 अप्रैल 2022
पेज थ्री
www.page3news.in

स्थानीय आरक्षण का देशव्यापी असर

विभिन्न उद्योग संगठनों ने यह कहते हुए इस कानून को चुनौती दी है कि इसके जरिए राज्य सरकार प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लागू करना चाहती है, जो एम्प्लॉयर्स के अधिकारों का उल्लंघन है। अब तक इन क्षेत्रों में नौकरी कैंडिडेट्स की योग्यता और स्किल के आधार पर दी जाती रही है।

सुमन वर्मा।।

हरियाणा में निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय प्रत्याशियों के लिए 75 फीसदी सीटें आरक्षित करने के फैसले को राज्य का मामला बताने की केंद्र सरकार कोशिश को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने ठीक ही खारिज कर दिया। केंद्र सरकार ने इस मामले में अदालत को बताया था कि चूंकि यह राज्य का कानून है, इसलिए केंद्र सरकार इस पर कोई स्टैंड लेना जरूरी नहीं समझती। लिहाजा, इस मामले में वह कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेगी। ध्यान रहे, हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एक्ट 2020 राज्य विधानसभा में पिछले साल मार्च में पारित हुआ और राज्यपाल की मंजूरी के बाद नवंबर में इसे श्रम विभाग द्वारा नोटिफाई भी कर दिया गया। इस कानून के मुताबिक, राज्य में निजी क्षेत्र की तमाम कंपनियों, ट्रस्टों, सोसाइटियों के तहत निकाली जाने वाली नौकरियों में 30,000 रुपये प्रति महीने या उससे कम वेतन वाले सभी पदों पर 75 फीसदी स्थान उन प्रत्याशियों के लिए आरक्षित होंगे, जो हरियाणा के निवासी हैं। इसके तहत वे सारी कंपनियां आ जाती हैं, जिनमें दस या उससे ज्यादा कर्मचारी हैं। विभिन्न उद्योग संगठनों ने यह कहते हुए इस कानून को चुनौती दी है कि इसके जरिए राज्य सरकार प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लागू करना चाहती है, जो एम्प्लॉयर्स के अधिकारों का उल्लंघन है। अब तक इन क्षेत्रों में नौकरी कैंडिडेट्स की योग्यता और स्किल के आधार पर दी जाती रही है।

साफ है कि इस कानून का सीधा प्रभाव देश भर के उन पढ़े–लिखे युवाओं की संभावनाओं पर भी पड़ेगा, जो अपनी काबिलियत के आधार पर देश के किसी भी हिस्से में जाने और काम करने की आकांक्षा रखते हैं। ऐसे में यह समझना मुश्किल है कि केंद्र सरकार इस कानून को एक राज्य का मामला आखिर कैसे करार दे सकती है। हालांकि इस तरह का कानून लाने के पीछे राज्य सरकार की यह वाजिब चिंता है कि वह अपने राज्य के युवाओं को रोजगार मुहैया कराने की अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पा रही। लेकिन यह तथ्य भी उतना ही स्पष्ट है कि देश के अन्य राज्यों की सरकारें भी ऐसी चुनौती से जूझ रही हैं। ऐसे में अगर एक राज्य ने ऐसे कानून में हल ढूंढने की कोशिश की तो अन्य सरकारें भी उसका अनुसरण करने में नहीं हिचकेंगी, जिसका नतीजा अंततरू इस रूप में सामने आ सकता है कि देश के युवाओं की आकांक्षाओं का आकाश अपने–अपने राज्यों की सीमाओं में कैद होकर रह जाए।

हैरत की बात है कि केंद्र सरकार इतने महत्वपूर्ण मामले को एक राज्य सरकार के मत्थे मढ़कर अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है। अच्छा है कि हाईकोर्ट ने पूरी सख्ती दिखाते हुए इस नजरिए को अस्वीकार्य बता दिया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि बुधवार को इस मामले की अगली सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के रुख में पॉजिटिव बदलाव दिखेगा।

महादेव का शिवलिंग

अशोक वोहरा।
भगवान शिव इस युद्ध को देख रहे थे। युद्ध को शांत करने के लिए भगवान शिव महाग्नि तुल्य स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। इसी महाग्नि तुल्य स्तंभ को काठगढ़ में विराजमान महादेव का शिवलिंग स्वरूप माना जाता है। इसे अर्द्धनारीश्वर शिवलिंग भी कहा जाता है। आदिकाल से स्वयंभू प्रकट सात फुट से अधिक ऊंचा, छह फुट तीन इंच की परिधि में भूरे रंग के रेतीले पाषाण रूप में यह शिवलिंग ब्यास व छौंछ खड्ड के संगम के नजदीक टीले पर विराजमान है। यह शिवलिंग दो भागों में विभाजित है। छोटे भाग को मां पार्वती तथा ऊंचे भाग को भगवान शिव के रूप में माना जाता है। मान्यता अनुसार मां पार्वती और भगवान शिव के इस अर्द्धनारीश्वर के मध्य का हिस्सा नक्षत्रों के अनुरूप घटता–बढ़ता रहता है और शिवरात्रि पर दोनों का मिलन हो जाता है।

संपादकीय

चीन का मकसद

बड़े लक्ष्य की पूर्ति के लिए क्वाड को अपनी ऊर्जा लगानी होगी। जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ शिखर बैठकों के बाद जारी साझा बयानों में इसी के अनुरूप एक समान शब्दावली में संकल्प जाहिर किया गया है। चीन ने भारत के साथ अपने रिश्तों को पटरी पर लाने और आला नेताओं के एक–दूसरे के यहां आने जाने का जो प्रस्ताव किया है उसकी टाइमिंग के मद्देनजर उसे क्वाड को कमजोर करने की एक कोशिश के रूप में भी देखा जा सकता है। चूंकि भारत के बिना क्वाड की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए भारत को यह देखना होगा कि वह क्वाड में अमेरिकी सामरिक हितों की पूर्ति करने वाला हथकंडा बन कर नहीं रह जाए। क्वाड के शिखर नेताओं की मौजूदगी वाली आगामी बैठक में भाग लेने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोकियो जाएंगे तब भारत का जोर इसी पहलू पर रहेगा कि हिंद प्रशांत के महासागरीय इलाकों में अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानूनों का पालन हो और इस इलाके को पूरी तरह समुद्री आवगमन के लिए खुला रखा जाए। इस इलाके में किसी एक देश यानी चीन की दादागीरी नहीं चले, क्वाड का यह भी एक बड़ा लक्ष्य है। लेकिन भारत की प्राथमिकता अपने राष्ट्रीय हितों के मद्देनजर स्वतंत्र विदेश नीति पर कायम रहते हुए क्वाड को मजबूत करने की ही रहेगी।

भारत पर यह दबाव बनाया जाएगा कि यूक्रेन के खिलाफ रूसी सैन्य हमले की स्पष्ट निंदा करने वाले बयान में शामिल हो लेकिन इसके पहले जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भारत के रुख के प्रति समझ दर्शाकर उसकी राजनयिक उलझनें कम कर दी हैं।

टोकियो शिखर बैठक

रंजीत कुमार।।

यूक्रेन संकट की पृष्ठभूमि में दुनिया के दो अहम संगठनों– क्वाड और ब्रिक्स को बचाने की इन दिनों गहन राजनयिक कोशिशें चल रही हैं। 19 मार्च को जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा और 21 मार्च को ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के साथ भारतीय प्रधानमंत्री की शिखर बैठक के बाद 24 मार्च को चीनी विदेश मंत्री वांग ई भारत आए। जापान और ऑस्ट्रेलिया ने यूक्रेन संकट पर भारत के रुख को नजरअंदाज करने का संकेत दिया ताकि चार देशों के हिंद प्रशांतीय संगठन क्वाड में कोई फूट नहीं पड़े। दूसरी तरफ चीन की कोशिश है कि इस साल के उत्तरार्द्ध में पेइचिंग में होने वाली ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) शिखर बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करें। मोदी यदि चीन नहीं जाते हैं तो ब्रिक्स के अस्तित्व पर आंच आएगी। टोकियो में होने वाली क्वाड शिखर बैठक में भाग लेना प्रधानमंत्री मोदी पहले ही मंजूर कर चुके हैं लेकिन वांग ई को भारत की ओर से कोई भरोसा नहीं दिया गया है कि मोदी चीन जाएंगे।

वैसे तो फुमियो किशिदा और स्कॉट मॉरिसन के भारत दौरे का घोषित उद्देश्य द्विपक्षीय सामरिक और आर्थिक रिश्तों को नई गहराई देना था लेकिन इस दौरान यूक्रेन संकट और क्वाड को

इससे अलग रखने के मसले पर होने वाली चर्चा पर सामरिक हलकों की नजरें टिकी रहीं। भारत की चिंता है कि क्वाड को यदि दुनिया के अन्य मसलों में घसीटा गया तो हिंद प्रशांत के इलाके में चीन द्वारा पैदा सामरिक चुनौतियों से निपटने का संकल्प कमजोर होगा। क्वाड के अन्य सदस्य देशों ने भी इससे सहमति जताई है। इसी पृष्ठभूमि में दो महीने के भीतर जब टोकियो में क्वाड के चारों शिखर नेताओं की सशरीर मौजूदगी होगी तब यूक्रेन मसले पर जम कर चर्चा होगी। भारत पर यह दबाव बनाया जाएगा कि यूक्रेन के खिलाफ रूसी सैन्य हमले की स्पष्ट निंदा करने वाले बयान में शामिल हो लेकिन इसके पहले जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भारत के रुख के प्रति समझ दर्शाकर उसकी राजनयिक उलझनें कम कर दी हैं।

दूसरी ओर ब्रिक्स को बचाने को लेकर चीन की चिंताएं बढ़ गई हैं। जैसे भारत के बिना क्वाड की कल्पना नहीं की जा सकती वैसे ही भारत के बिना ब्रिक्स की भी कल्पना नहीं की जा सकती। लद्दाख सीमा पर चीनी सैनिक अतिक्रमण जारी रहने की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यदि चीन का निमंत्रण स्वीकार नहीं करते हैं तो ब्रिक्स शिखर बैठक नहीं हो पाएगी। ऐसे में अमेरिका विरोधी गुट को मजबूत करने की चीन की मंशा पर पानी फिरेगा। लेकिन भारत की प्राथमिकता क्वाड को बचाने की है। हालांकि ब्रिक्स का गठन दो दशक पहले जब हुआ था तब कई पर्यवेक्षकों ने इसे अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती देने वाले एक समहू के तौर पर देखा था। रोचक बात यह भी है कि ब्रिक्स के दो अन्य सदस्यों दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील ने भी रूसी सैनिक कार्रवाई की सीधी निंदा नहीं की है। लेकिन इसके बावजूद मौजूदा हालात में भारत रूस के समर्थन में ब्रिक्स के बैनर तले चीन के साथ खड़ा नहीं दिख सकता।

बहरहाल, क्वाड का सदस्य होने के बावजूद यूक्रेन संकट पर भारत का खुलकर रूस की निंदा नहीं करना अमेरिका को काफी खटक रहा है। गत तीन मार्च को अमेरिका ने क्वाड की वर्चुअल शिखर बैठक आयोजित की थी जिसका एक मकसद क्वाड की ओर से रूस की निंदा वाला प्रस्ताव पारित करवाने के लिए भारत पर दबाव डालना भी था।

सूडोकू नवताल- 5271

मध्यम

		5			8			
	7			3	5			
3						6		
							8	5
	6						1	
4	2							
		1						8
			7	4			3	
			2			7		

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं।
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें।
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते।
- पहेली का केवल एक ही हल है।

सूडोकू नवताल -5270 का हल

5	7	4	1	3	9	6	2	8
2	8	9	6	5	7	1	4	3
3	6	1	2	8	4	5	7	9
9	3	7	8	1	6	4	5	2
6	5	8	4	9	2	3	1	7
1	4	2	5	7	3	8	9	6
7	9	6	3	4	1	2	8	5
4	2	5	9	6	8	7	3	1
8	1	3	7	2	5	9	6	4

अपना ब्लॉग

स्पष्ट निंदा वाला प्रस्ताव नहीं पारित किया

मोहन। भारत के इस रुख के मद्देनजर ही पिछली क्वाड वर्चुअल शिखर बैठक के बाद जारी साझा बयान में रूस की स्पष्ट निंदा वाला प्रस्ताव नहीं पारित किया गया। रूस के खिलाफ अमेरिकी सामरिक खेल में भारत ने उसके पक्ष में खेलने से साफ इनकार कर दिया तो इसकी कई जायज वजहें हैं। भारतीय सामरिक हलकों की यह शिकायत रही है कि क्वाड का सदस्य होने के नाते भारत भी यह अपेक्षा कर सकता था कि भारतीय सीमांत इलाकों में चीनी सैनिक अतिक्रमण के खिलाफ क्वाड की ओर से कोई निंदात्मक बयान जारी किया जाता। लेकिन भारत ने साफ कहा कि हिंद प्रशांत के चार देशों वाले इस गुट का फोकस हिंद प्रशांत इलाके पर ही सीमित रखा जाए अन्यथा क्वाड अपने घोषित उद्देश्य से भटक जाएगा और दुनिया के अन्य मसलों में उलझ कर रह जाएगा। इससे चीन को दक्षिण और पूर्वी चीन सागरीय इलाके में अपना प्रभुत्व मजबूत करने का मौका मिलेगा। चीनी अतक्रिमण को रोकने के लिए कोई प्रत्यक्ष और ठोस कदम भारत के पक्ष में उठाने की बात तो दूर भारत का मनोबल बढ़ाने वाला बयान भी क्वाड के किसी शिखर नेता ने नहीं जारी किया।